



Skill Development Programme

For Answer Writing

Env. & Eco. (Model Answer)

DATE : 12-June-2018

TIME : 03:15 PM

मुख्य परीक्षा

- प्र. “पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) को लगभग एक दशक पूरा हो गया है लेकिन फिर भी भारत में EIA प्रक्रिया अपरिपक्व है।” इस कथन की विवेचना कीजिए तथा EIA रिपोर्ट को बेहतर किए जाने वाले समाधानों को भी स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

"Environmental Impact Assessment (EIA) has completed one decade, but then also the process of EIA in India is in immature stage." Analyze this statement and explain the settlements which can improve EIA report. (250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) को स्पष्ट करें।
- अगले पैरा में बताएं कि दस साल के बाद भी EIA क्यों अपरिपक्व है?
- फिर अगले पैरा में इसके समाधानों को स्पष्ट करें।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

उत्तर- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) योजना निर्माताओं को उपलब्ध एक उपकरण है, ताकि विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच एक समन्वय हो सके। भारत में EIA का आरम्भ 1978-79 में नदी घाटी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से हुआ और कालांतर में इसके दायरे में उद्योग, ताप, विद्युत परियोजनाएँ आदि को शामिल किया गया। वर्ष 2006 में केंद्र सरकार द्वारा EIA अधिसूचना जारी की गई जिसके तहत परियोजनाओं के लिए EIA रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य कर दिया।

जिन राज्यों में राज्य प्राधिकरण नहीं है, उनकी परियोजना की सूची केंद्रीय मंत्रालय तय करता है। EIA रिपोर्ट पर अंतिम फैसला केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय और राज्य में EIA प्राधिकरण करता है।

EIA रिपोर्ट अपरिपक्व क्यों है?

- रिपोर्ट बनाने वाली कम्पनियों में मानव संसाधन की कमी तथा उनका भ्रष्ट व्यवहार।
- पुरानी रिपोर्ट के आकड़ों को ही कॉपी किया जाना।
- परामर्श समितियों में विशेषता का अभाव तथा समितियों द्वारा जनसलाह की अनदेखी करना।
- जनसलाह के दौरान जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन और EAC को निष्पक्ष न रख पाना।
- परामर्श समितियों का केवल सलाहकारी भूमिका होना।
- मूल्यांकन के अंतिम फैसले को लगातार कोर्ट में चुनौती दिया जाना।
- इस रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख उदाहरण- नियमागिरी पहाड़ी मामला, केन-वेतवा लिंक, INO (Indian Neutrino Observatory) तमिलनाडु वेदांता संयंत्र आदि।

समाधान-

- परामर्श समिति में सिविल सोसाइटी व NGO के लोगों को शामिल किया जाए।
- EIA रिपोर्ट तैयार करने वाली कम्पनियों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए।
- बेहतर जन सुनवाई के लिए EIA रिपोर्ट सरल व स्थानीय भाषा में तैयार की जाए।
- EIA प्रक्रिया को समयबद्ध सीमा में पूरा किया जाए।

